स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–20, अंक–4, चैत्र–वैशाख 2069, अप्रैल 2012

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–4

एक जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में व्यापक भुखमरी और गरीबी के मद्देनजर आश्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार गरीबी की एक नितांत अव्यवहारिक परिभाषा अपना रही है.

अनुक्रम

आवरण कथा

विकास का असर या आंकड़ों की बाजीगरी
– डॉ. अश्विनी महाजन /4

कृषि

विज्ञान का लोकतांत्रिक चेहरा
– वंदना शिवा /6

अर्थव्यवस्था

ईरान के तेल का विकल्प
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /8

अंतर्राष्ट्रीय

सीरिया के चलते बढ़ता वैश्विक तनाव
– अवधेश कुमार /11

विचार–विमर्श

उपलब्धियों से वंचित ब्रिक्स
– ब्रह्म चेलानी /14

विषमता

आर्थिक विषमता का चिंताजनक दौर
– जयंतीलाल भंडारी /17

सवाल–जवाब

मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ
– वेद प्रताप वैदिक /20

जनता का फैसला

सपा के अखिलेश यादव को जनाकांक्षाओं पर स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /21

पर्यावरण

गंगा के प्रति शून्य संवेदना
– राजेन्द्र सिंह /24

देख रही हो गंगा माई, अब हम हवा में उड़ रहे हैं
– रवीश कुमार /26

धरोहर : रामसेतु को बचाइये
– निरंकार सिंह /27

स्मरण

श्रद्धेय दत्तोपंत जी का अलौकिक सान्निध्य
– डॉ. रणजीत सिंह /30

पाठकनामा/2, रपट/34

पाठकनामा

आंकड़ों के जाल पर न जाकर, सरकार महंगाई को लगाए रोक

स्वदेशी पत्रिका अपने प्रत्येक अंक में देश की समस्याओं के बारे में कोई न कोई लेख अवश्य प्रकाशित करती रहती है जिससे पाठकों को देश की समस्याओं के बारे में पता चलता है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है – गरीबी। परंतु केन्द्र में बैठी सरकार, हमेशा गरीबों का मजाक ही उड़ाती रहती है। वर्ष 2009–10 में योजना आयोग की रिपोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में 32 रूपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 प्रतिदिन खर्च करने वाले को गरीब माना। वही दूसरी तरफ हम देखें तो आज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में रहने वाला एक छोटा परिवार अर्थात् पति–पत्नी और दो बच्चे वाला परिवार जो 15 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता हो और इन शहरों में किराये के मकानों में रहता हो, तो इनका गुजारा करना भी काफी मुश्किल होता है। फिर सरकार किस प्रकार गरीबी का आंकड़ा पेश करती है जिससे देश में रह रहे गरीबों का केवल मजाक ही उड़ाया जाता है। अभी हाल ही में एक जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में व्यापक भुखमरी और गरीबी के मद्देनज़र आश्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार गरीबी की एक नितांत अव्यवहारिक परिभाषा अपना रही है जिसके कारण जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज वर्तमान सरकार, केवल गरीबी पर, केवल राजनीति कर रही है। उसे देश में रह रहे गरीबों की कोई चिंता नहीं है, उसे तो केवल गरीबों का मजाक उड़ना आता है जबकि आज गरीबों की आय महंगाई के चलते दिन–प्रति–दिन गिरती जा रही है। जहां सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए थी, वही वह दिन–प्रति–दिन गरीबी के आंकड़ों का विवरण देती रहती है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी।

– सुधीर रावत, फैबटेक ईवेन्ट सर्विस, अभय खण्ड–4, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

शराब पर रोकथाम है जरूरी

आज देश में शराब पर पाबंदी जरूरी हो गई है। हर दिन अखबारों में अपराधों की खबर दिन–प्रति–दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी चंद रुपयों की खातिर, तो कभी बदले की भावना से आदमी, आदमी को मार रहा है। इन हत्याओं और दुष्कर्मों की कहीं न कहीं सबसे बड़ी वजह नशाखोरी, चाहे वह शराब हो या अन्य तरह का जिसकी खुमारी व्यक्ति को आदमी, आदमी का अंतर भूलने पर मजबूर कर देता है। नशाखोरी से आदमी की सही गलत सोचने व समझने की क्षमता को बंद कर देता है और वह इतने बड़े अपराध कर बैठता है। एक सर्वे के अनुसार आज 75 से 80 प्रतिशत अपराध शराब पीने की वजह से होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है कि यहां का युवा वर्ग अपने पूरे दिनभर में पानी से ज्यादा शराब पीते हैं जिससे वे अपने आसपास का सामाजिक माहौल तक भी ताक पर रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में अपराध का ग्राफ सबसे कम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां शराब पर रोकथाम है जिसके कारण वह प्रदेश सफलताओं की ऊंचाईयों पर आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित सभी राज्य सरकारों को भी शराब पर रोकथाम करना अनिवार्य है। सरकार अपना फायदा न देखकर जनता का फायदा देखें तभी सरकार इन अपराधों को कम कर सकती है। – राकेश कुमार दास, अभयखण्ड–4, मीडियाअपार्टमेन्ट, गाजियाबाद।

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

जिस दिन हमारे लोकसेवकों को यह अहसास हो जाएगा कि उन्हें इज्जत मांगने से नहीं, बल्कि कमाने से मिलेगी, उस दिन लोगों की सेवा का नजरिया ही बदल जाएगा।

– किरण बेदी

सेना प्रमुख को इस बात के लिए सलाम कि उन्होंने रिश्वत के मामले का खुलासा किया। कम से कम हमारे पास एक ऐसा प्रमुख है जो देश की सेवा करता है, नेताओं की नहीं।

– चेतन भगत

बजट की तरह नया कोयला घोटाला भी आज का मतदाता देखें कि देश में अर्थव्यवस्था किस तरह चौपट हो रही है।

– संतोष गंगवार

गरीबी निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति की आलोचना कर रहे सांसद शायद यह समझते है कि यह सचिन तेंदुलकर समिति है। वे सुरेश तेंदुलकर को जानते ही नहीं।

– जयराम रमेश

भारतीय संस्कृति में गाय का स्थान 'मां' से कम नहीं है। उससे प्राप्त होने वाला हरेक चीज काफी उपयोगी, लाभप्रद और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब **गो–हत्या प्रतिबंध में कोताही बर्दाश्त नहीं ।**

– सत्यानंद झा 'बादल'

विदेशी निवेश नहीं नीति की सही दिशा चाहिए

कुछ दिन पहले जब ब्रिक्स देशों के शासनाध्यक्ष स्थानीय करेंसी में आपसी व्यापार करने और ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने के संबंध में निर्णय लेते हुए डॉलर, यूरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों को चुनौती देने का काम कर रहे थे, वही भारत सरकार निजी विमानन कंपनियों को राहत देने के नाम पर उनके 49 प्रतिशत शेयरों को विदेशी हाथों में बेचने की नीति को हरी झण्डी दिखाने की तैयारी कर रही थी। मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश न लागू करवा पाने की कुण्ठा में विमानन क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की नीति को सरकार आर्थिक सुधार का नाम देने की कोशिश कर रही है।

देश विविध क्षेत्रों में विदेशी निवेश की नीति के नतीजे पहले से ही भुगत रहा है। सीमेण्ट क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एसीसी कंपनी के विदेशियों द्वारा अधिग्रहण के चलते देश में सीमेण्ट की कीमतों में लगातार अनाप–शनाप वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बार–बार चेताने के बावजूद विदेशियों द्वारा दवा कंपनियों के अधिग्रहण पर भारत सरकार द्वारा रोक न लगाए जाने के कारण देश में जेनेरिक दवाईयों की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते देश का जन–स्वास्थ्य खतरे में पड़ चुका है। आज भारत की विमानन कंपनियां प्रबंधन अकुशलता से कम, महंगे ईंधन से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, सरकार द्वारा विदेशी निवेश की नीति ही एक मात्र समाधान मानी जा रही है। जरूरत इस बात की है कि विमान ईंधन पर टैक्स घटाकर उसे सस्ता करते हुए, विमानन कंपनियों की परिचालक लागत घटायी जाए। भारत की विमानन कंपनियों को विदेशी हाथों को सौंपा जाना देश के लोगों की सस्ती वायु यात्रा की आकांक्षाओं पर एक कुठाराघात होगा।

आज देश की अर्थव्यवस्था सरकार की प्रबंधन अकुशलता के कारण संकट में पड़ गई है। रूपए का अवमूल्यन और बढ़ती कीमतें किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं बल्कि सरकार की गलतियों का नतीजा है। सरकार निर्यात बढ़ने के नाम पर अपनी पीठ ठोंकने का काम कर रही है। लेकिन बढ़ते आयातों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। बढ़ता व्यापार घाटा देश पर कर्ज बढ़ा रहा है। उधर सरकार द्वारा अपने खर्चों पर अंकुश न लगा पाने के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ व्यापार घाटा और दूसरी ओर राजकोषीय घाटा, दोहरे घाटों के चलते आज अर्थव्यवस्था भारी मुश्किल में दिखाई दे रही है। उधर महंगाई से घबराकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को लगातार बढ़ाने की नीति देश में मांग पर दुष्प्रभाव डाल रही है। लगातार स्थिर औद्योगिक उत्पादन देश की चिंताओं को और बढ़ा रहा है।

समय की मांग है कि सरकार अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन हेतु प्रयास करे और यह समझे कि हर मुश्किल का हल विदेशी निवेश नहीं होता। हां विदेशी निवेश हमारी मुश्किलें बढ़ा जरूर सकता है।

विकास का असर या आंकड़ों की बाजीगरी

सरकार का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के चलते भी गरीबी का प्रकोप घटा है। लेकिन यदि हम मामले की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में सरकार द्वारा अभी भी गरीबी की वही गलत परिभाषा अपनाई जा रही है, जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने घोर आपत्ति दर्ज की थी। संसद में तो विरोधी पार्टियों ने इस कृत्य के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के त्याग–पत्र की मांग तक की है।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

एक जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में व्यापक भुखमरी और गरीबी के मद्देनजर आश्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार गरीबी की एक नितांत अव्यवहारिक परिभाषा अपना रही है, जिसके अनुसार वर्ष 2004–05 में मात्र 37 प्रतिशत लोग ही गरीब थे।

यह तो गनीमत है कि प्रो. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल ने गरीबी की एक बेहतर परिभाषा दी, अन्यथा भारत सरकार की पूर्व की परिभाषा के अनुसार तो 2004–05 में मात्र 27.5 प्रतिशत लोग ही गरीब रह गये थे। प्रो. तेंदुलकर की परिभाषा के अनुसार भी वर्ष 2004–05 में शहरी क्षेत्रों में 578.8 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 446.7 रूपये से अधिक पाने वाले गरीबी की परिभाषा में नहीं आते।

जब सर्वोच्च न्यायालय ने योजना आयोग को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा तो भी योजना आयोग ने वर्ष 2009–10 के लिए गरीबी की परिधि में आने लायक आय को शहरी क्षेत्रों में 32 रूपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 प्रतिदिन ही माना।

ऐसे में जब देश में महंगाई के बोझ के तले दबी आम जनता का जीना दूभर हो गया है, सरकार के गरीबी के परिभाषा के संबंध में इस अड़ियल रूख के चलते सरकार की पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी थी। जबकि गरीबी की इस परिभाषा के मद्देनजर देश में एक बहस शुरू हो चुकी है कि क्या सरकार गरीबों और गरीबी निवारण के प्रति संवेदनशील है भी कि नहीं, योजना आयोग द्वारा हाल ही में जारी गरीबी के आकड़ों ने तो जैसे पुराने जख्म पर फिर से नमक डाल दिया है।

सोमवार 21 मार्च 2012 को जारी आकड़ों के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 2004–05 में जनसंख्या के 37 प्रतिशत से घटते हुए अब लगभग 30 प्रतिशत ही रह गई है। सरकार द्वारा इन आंकड़ों को औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है।

योजना आयोग का कहना है कि देश में तेजी से हुई आर्थिक प्रगति और सरकार द्वारा चलाये जा रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम, जिसमें हर वर्ष 100 रूपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, के चलते यह गरीबी घटी है। सरकार का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के चलते भी गरीबी का प्रकोप घटा है।

लेकिन यदि हम मामले की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में

सरकार द्वारा अभी भी गरीबी की वही गलत परिभाषा अपनाई जा रही है, जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने घोर आपत्ति दर्ज की थी। संसद में तो विरोधी पार्टियों ने इस कृत्य के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के त्याग–पत्र की मांग तक की है।

आलोचकों का कहना है कि योजना आयोग ने अत्यंत गैर जिम्मेदारीपूर्वक एक गरीबी की रेखा की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। नई परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति जो शहरी क्षेत्रों में 28.7 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 22.5 रूपये दैनिक आमदनी प्राप्त करता है, वो गरीबी की रेखा से ऊपर माना जायेगा।

गौरतलब है कि योजना आयोग स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर यह कह चुका है कि शहरी क्षेत्रों में 32 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 28 रूपये से कम पाने वाला गरीबी की रेखा से नीचे माना जायेगा। ऐसे में 2004–05 से 2009–10 के बीच जबकि कीमतें ही 60 प्रतिशत बढ़ गई तो गरीबी की रेखा कैसे नीचे पहुंच गई, यह समझ के परे है।

जाहिर है कि परिभाषा बदलते हुए आकड़ों की कारीगरी से तो गरीबी को किसी भी स्तर पर लाया जा सकता है, उसमें सरकार द्वारा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गरीबी की रेखा को बदलते हुए अचानक गरीबी को घटाने की कवायद कोई नई बात नही है। इससे पहले भी सर्वप्रथम सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में गरीबी की परिभाषा को बदलते हुए गरीबी के आंकड़ों को कम दर्शाने का प्रयास हुआ था और यह अभी तक चल रहा है।

सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2004–05 से 2009–10 के बीच 8.9 प्रतिशत औसत आर्थिक संवृद्धि के फलस्वरूप गरीबों की प्रतिशत की संख्या घटना स्वाभाविक ही है। और इस कारण वर्ष 2004–05 में जहां गरीबों की संख्या 40.7 करोड़ थी, वह घटकर 2009–10 में 35.5 करोड़ ही रह गई। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी नरेगा सरीखी योजनाओं के कारण ज्यादा तेजी से घटी है।

लेकिन जहां तक सरकार का यह तर्क है कि गरीबी का घटना नरेगा के कारण हुआ है, शायद सही नहीं है। सरकार का कहना है कि चूंकि नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4.8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये। लेकिन नरेगा और गरीबी का संबंध धरातल पर दिखाई नहीं देता और न ही ऐसा दिखाई देता है कि आर्थिक संवृद्धि गरीबी को घटा रही है।

उदाहरण के लिए बिहार द्वारा 2004–05 से 2009–10 के कालखंड में 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से आर्थिक संवृद्धि रिकार्ड की गई, लेकिन वहां गरीबी नहीं घट पाई। सरकारी तंत्र का कहना है कि शायद नरेगा में बिहार का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण ऐसा हुआ।

जहां मध्यप्रदेश में नरेगा को गरीबी घटने का कारण बताने का प्रयास हो रहा है तो महाराष्ट्र और उड़ीसा में आर्थिक संवृद्धि को गरीबी घटाने के लिये जिम्मेवार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश और असम में नीची आर्थिक संवृद्धि और नरेगा के धन का कम उपयोग दोनों गरीबी न घटने के लिये जिम्मेवार बताये जा रहे हैं।

अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग गरीबी घटने के आंकड़ों को पूरी तरह से मानने के लिये तैयार नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री हालांकि गरीबी घटने की बात आंशिक रूप से तो मानते हैं, तो भी उनका कहना है कि गरीबी में इतनी कमी नहीं मानी जा सकती। उनका मानना है कि गरीबी की रेखा को परिभाषित करने में गलती हुई है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि गरीबी की रेखा में कुछ गलती हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों और राष्ट्रीय लेखा के आंकड़ों के बीच में गंभीर अंतर है। हालांकि उन्होंने इसे सांख्यिकी संबंधी समस्या बनाकर टाल दिया है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह गड़बड़ झाला वास्तव में सरकार की ईमानदारी पर संदेह खड़ा करता है, क्योंकि इसके द्वारा गरीबों की संख्या को कम आंकने का प्रयास किया गया है।

लेकिन एक विषय जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, वह है, देश में बढ़ती असमानताएं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में औसत आमदनी बढ़ी है। आज देश की प्रति व्यक्ति आय (चालू कीमतों पर) लगभग 53,000 रूपये प्रति वर्ष पहुंच चुकी है। लेकिन यह गरीबी घटाने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं है।

ऐसा इसलिये है कि गरीब आदमी की आय में उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही क्योंकि देश में आय की असमानताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी 2004–05 से 2009–10 के बीच 5 वर्षों में आय की असमानताएं तेजी से बढ़ी हैं। आय की असमनताओं का सूचक गिनी चरांक 0.35 से बढ़कर 0.37 हो गया है। असमानताओं में यह वृद्धि सभी प्रांतों में दिखाई देती है। ❑

विज्ञान का लोकतांत्रिक चेहरा

प्रधानमंत्री 'दोहरी मार' की चर्चा तो करते हैं, लेकिन वह इसे एक 'अवसर' के रूप में भी देखते हैं। वह अब तक ढाई लाख किसानों की आत्महत्या, देश में गहराते कृषि और खाद्य संकट और बच्चों की कुल संख्या की आधी फीसदी आबादी के कुपोषित होने जैसे मसलों का हल तलाशने में विफल रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि जीएमओ इन समस्याओं का समाधान नहीं है। जीएमओ बीजों के एकाधिकार पर आधारित पूंजीगत गैर-टिकाऊ कृषि से जुड़े कर्ज संकट को और बढ़ा रहा है।

■ वंदना शिवा

हाल ही में साइंस पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया था कि देश में विज्ञान के विकास के लिए दो तकनीकों पर ध्यान देना जरूरी है – पहला कृषि में जीई (जेनेटिक इंजीनियरिंग) बीज और फसल का उपयोग तथा दूसरा परमाणु ऊर्जा।

दुर्भाग्य से, हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए ये दोनों ही तकनीकें खतरनाक हैं। तब प्रधानमंत्री ने गैरसरकारी संगठनों पर भी उंगली उठाते हुए कहा था कि ये संस्थाएं विदेशी हाथों में खेल रही हैं और 'विकास कार्यों' में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

प्रधानमंत्री का यह बयान बताता है कि वह न सिर्फ विज्ञान से दूर हैं, बल्कि आम लोगों से भी दूर हैं, लोकतंत्र में जिसके प्रतिनिधित्व का वह दावा करते हैं।

बल्कि ऐसी खतरनाक तकनीकों के इस्तेमाल को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे एनजीओ में 'विदेशी पूंजी' लगने की बात कहकर वह देश को गुमराह करने का काम ही रहे हैं। जिम्मेदार और लोकतांत्रिक विज्ञान के विकास की दिशा में प्रधानमंत्री को डॉ पुष्प भार्गव (देश में आणविक जीव विज्ञान के जनक और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि), डॉ. ए. गोपाल कृष्णन (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व चेयरमैन) जैसे विशेषज्ञों की राय सुननी चाहिए, न कि 'विदेशी हाथ' का हौवा खड़ा कर उन सामाजिक आंदोलनों अथवा जन हितैषी समूहों पर चोट करनी चाहिए, जो किसी भी लोकतंत्र में खून की तरह हैं।

दरअसल, देश में जीएमओ (जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म) और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को प्रमुखता से आगे बढ़ाने के लिए ही उन आंदोलनों को कुचला जा रहा है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और

पहला कृषि में जीई (जेनेटिक इंजीनियरिंग) बीज और फसल का उपयोग तथा दूसरा परमाणु ऊर्जा। दुर्भाग्य से, हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए ये दोनों ही तकनीकें खतरनाक हैं। तब प्रधानमंत्री ने गैरसरकारी संगठनों पर भी उंगली उठाते हुए कहा था कि ये संस्थाएं विदेशी हाथों में खेल रही हैं और 'विकास कार्यों' में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाया जाता है। निर्विवाद है कि ये हमले विदेशी कॉरपोरेट घरानों की शह पर हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी इन घरानों के दबाव में आकर देश की खाद्य और ऊर्जा संप्रभुता से समझौता करने को तैयार हो गए हैं।

उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया, जिसका संसद से अनुमोदन 'वोट के बदले नोट' कांड के बाद ही हो सका। इसी तरह हमारी सरकार ने अमेरिका के साथ खेती से जुड़ा करार किया, जिसमें हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्थाओं को मोनसेंटो, कारगिल और वॉलमार्ट जैसी विदेशी कॉरपोरेट के हाथों बंधक हो जाना है।

बहरहाल, संसद ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लागू करने की कोशिशें विफल कर दीं। आम लोगों ने भी विधानसभा चुनावों में बता दिया कि वे केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ हैं, जो वैश्विक निगमों के हितों का पोषण करती हैं, क्योंकि ये नीतियां आजीविका खत्म कर रही हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रही हैं।

हमने पहले ही देखा कि मोनसेंटो के आने के बाद किस तरह कपास के बीज पर अपनी संप्रभुता समाप्त हुई। आज कपास के हमारे बीजों का 95 फीसदी मोनसेंटो खरीद लेती है। नतीजतन देश में कपास बीजों की लागत 8,000 फीसदी बढ़ी, कपास की फसल के खराब होने की आशंका बढ़ी, कीटाणुनाशकों का प्रयोग बढ़ा, किसानों पर कर्ज बढ़ा और किसान–आत्महत्या महामारी के रूप में उभरी।

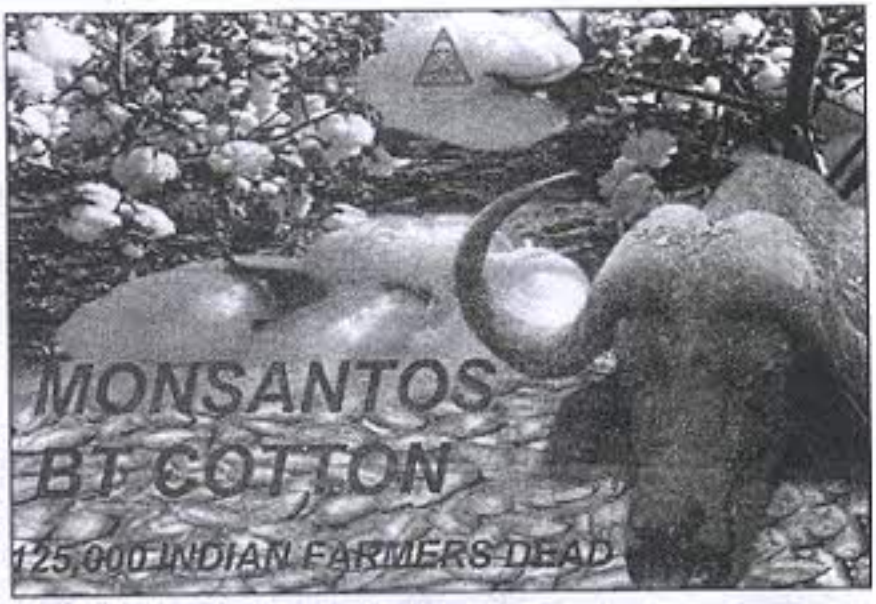

प्रधानमंत्री इस 'दोहरी मार' की चर्चा तो करते हैं, लेकिन वह इसे एक 'अवसर' के रूप में भी देखते हैं। वह अब तक ढाई लाख किसानों की आत्महत्या, देश में गहराते कृषि और खाद्य संकट और बच्चों की कुल संख्या की आधी फीसदी आबादी के कुपोषित होने जैसे मसलों का हल तलाशने में विफल रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि जीएमओ इन समस्याओं का समाधान नहीं है। जीएमओ बीजों के एकाधिकार पर आधारित पूंजीगत गैर–टिकाऊ कृषि से जुड़े कर्ज संकट को और बढ़ा रहा है।

इससे स्वस्थ और पोषक खाद्य पदार्थों से भरपूर हमारा खाद्य तंत्र नष्ट हो रहा है। असल में, किसानों की आत्महत्या और बाल कुपोषण जैसी समस्याओं के हल कृषि पारिस्थितिकी के विज्ञान और पारिस्थितिकी अनुकूलता के विकास में छिपे हैं। रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम होने से स्वाभाविक रूप से उत्पादन लागत कम होगी और उसमें पोषक तत्व भी होंगे।

लिहाजा यह कहना गलत नहीं कि समाज और पारिस्थितिकी की कीमत पर एक विफल तकनीक को 'विज्ञान' के नाम पर लागू किया जा रहा है, जो विरोधी–विज्ञान और अलोकतांत्रिक है। यह इसलिए भी विरोधी–विज्ञान है, क्योंकि वास्तविक विज्ञान कृषि–पारिस्थितिकी और जीनों में आनुवांशिक बदलाव के नए नियमों पर आधारित होता है, न कि आनुवांशिक नियतिवाद के अप्रचलित विचारों पर।

इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में नया विज्ञान अक्षय ऊर्जा है, न कि आणविक ऊर्जा। मगर क्या वैश्विक कॉरपोरेट घरानों से प्रभावित प्रधानमंत्री देश की बीज संप्रभुता, खाद्य संप्रभुता, ऊर्जा संप्रभुता और स्वास्थ्य तथा पोषण संप्रभुता को नष्ट करने वाली नीतियों को रोकेंगे? इस परिदृश्य में देखें, तो साइंस में दिया गया प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लोकतंत्र और लोक अधिकारों पर हो रहे हमले का ही एक हिस्सा है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक कॉरपोरेट घरानों की भूमिका को अलोकतांत्रिक तरीके से स्थापित किया जाता है। ❑

ईरान के तेल का विकल्प

ईरान से आयात जारी रखने पर अमरीका हमसे नाराज हो जायेगा और उससे हमें मिलने वाली पूंजी तथा तकनीक बाधित होगी। मेरी दृष्टि से यह प्रभाव नगण्य होगा। भारत पूंजी का निर्यातक बन चुका है। हमारे उद्यमियों द्वारा विदेशों में निवेश अधिक किया जा रहा है। फिर भी जो पूंजी आ रही है उसमें कटौती होने की सम्भावना है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

अमरीका की शिकायत ईरान के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को लेकर है। ईरान ने परमाणु अप्रसार ट्रीटी पर दस्तखत कर रखे हैं। ईरान का कहना है कि वह कामर्शियल उर्जा के उत्पादन के लिये परमाणु रियेक्टर लगा रहा है। अमरीका का मानना है कि यह ऊपरी आवरण है।

वास्तव में ईरान परमाणु अस्त्र बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों तथ्य के बीच सत्य का पता लगाना कठिन है।

अमरीका की स्ट्रेटजी ईरान के मध्य वर्ग को भड़काने की दिखती है। ईरान की घेरेबन्दी करके अमरीका उस देश को डुबोना नहीं चाहता है। पूर्व में ऐसा उत्तरी कोरिया के साथ किया गया था। कोरिया को फर्टिलाइजर और तेल की उपलब्धि बाधित कर दी गयी थी। फलस्वरूप वहां की खेती चौपट हो गयी। भीषण अकाल पड़ा और अनेक लोग काल कलवित हो गये। अन्ततः पश्चिमी देशों को खाद्य

उर्जा संकट गहराने के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने तेल के बढ़ते वैश्विक दामों को भारत और चीन द्वारा तेल की बढ़ती खपत के कारण बताया है। इंडोनेशिया एवं आस्ट्रेलिया जैसे निर्यातक देशों ने कोयले के दाम में वृद्धि की है। अपनी उर्जा की जरूरतों के लिये हम आयातों पर निर्भर हैं।

उर्जा के चार प्रमुख स्रोत हैं कोयला, यूरेनियम, तेल तथा जलविद्युत। हमारे कोयले के भंडार लगभग 200 वर्षों के लिये पर्याप्त हैं। परन्तु हमारे कोयले की क्वालिटी घटिया है। यदि हम कोयले का अति दोहन करेंगे तो 50 से 100 वर्षों में ही यह समाप्त हो जायेगा और हम ज्यादा कठिन परिस्थिति में अपने को पायेंगे।

यूरेनियम तथा तेल हमें लगभग पूर्णतया आयात करना पड़ता है। जलविद्युत के उत्पादन में हमारा पर्यावरण और संस्कृति नष्ट होती है। इस पृष्ठभूमि में हमें अमरीका द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि ईरान से तेल का आयात कम करें।

अमरीका की स्ट्रेटजी ईरान के मध्य वर्ग को भड़काने की दिखती है। ईरान की घेरेबन्दी करके अमरीका उस देश को डुबोना नहीं चाहता है। पूर्व में ऐसा उत्तरी कोरिया के साथ किया गया था। कोरिया को फर्टिलाइजर और तेल की उपलब्धि बाधित कर दी गयी थी। फलस्वरूप वहां की खेती चौपट हो गयी।

सामग्री पहुंचानी पड़ी। अमरीका सैन्य कार्यवाही भी नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे मुस्लिम वर्ल्ड में गलत मैसेज जायेगा।

ईराक और अफगानिस्तान की तुलना में ईरान बड़ा देश है जिसे फतह करना कठिन होगा। अतः अमरीका की स्ट्रेटजी है कि ईरान के मध्यम वर्ग पर दबाव बनाओ।

ईरान मध्य वर्गीय खपत के लिये इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे माल का आयात करता है। इसका भुगतान तेल के निर्यात से मिली रकम से किया जाता है। तेल का निर्यात बाधित होने पर ईरान द्वारा मध्य वर्ग के खपत की पूर्ति करना कठिन हो जायेगा। संभव है कि तब यह वर्ग अपने शासकों के विरूद्ध खड़ा हो जाये।

अमरीका द्वारा उन सभी देशों पर दबाव बनाया जा रहा है जो ईरान से तेल का आयात कर रहे हैं। वर्तमान में भारत, चीन तथा जापान द्वारा ईरान का 45 प्रतिशत तेल खरीदा जा रहा है। अमरीका और जापान के बीच समझौता होने का समाचार है जिसके अंर्तगत जापान द्वारा ईरान से आयातित तेल में 11 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

खबर है कि भारत सरकार ने भी तेल कम्पनियों को 10 प्रतिशत कटौती करने को कहा है। ईरान के पास तेल का भारी स्टाक एकत्रित हो गया है चूंकि यूरोप को निर्यात बन्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कठिन है कि यह दबाव ईरानी सरकार के विरूद्ध भड़केगा या अमरीका के विरूद्ध। पूर्व में ऐसी ही परिस्थिति में ईरान के लोगों ने अमरीकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था।

ऐसे में हमें तय करना है कि हम ईरान से तेल के आयात में कटौती करें या नहीं? पहला बिन्दु उर्जा सुरक्षा का है। हमारी उर्जा की बढ़ती खपत को देखते हुये ईरान से आयात में कटौती करना कष्टप्रद होगा। हमें दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना होगा जिससे महंगाई बढ़ेगी।

दूसरा बिन्दु देश के मुसलमानों की भावनाओं का है। इनका झुकाव निःसंदेह ईरान की ओर है। भारत सरकार के द्वारा ईरान के विरूद्ध कदम उठाने से हमारे मुसलमान भाई क्षुब्ध होंगे। तीसरा बिन्दु पाकिस्तान–अफगानिस्तान–ईरान के समूह का है। पाकिस्तान को घेरने में ईरान हमारी मदद कर सकता है। ईरान के हमारे विमुख होने पर अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा।

चौथा बिन्दु तेल के पेमेन्ट का है। ईरान ने निर्यातित तेल की रकम का 45 प्रतिशत रुपयों में लेना स्वीकार किया है। सामान्यतया हम आयातित तेल का पेमेन्ट डालर अथवा दूसरी परिवर्तनीय मुद्रा में करते हैं। अर्थात् बासमती चावल, साफ्टवेयर तथा मसालों के निर्यात से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इस मुद्रा को तेल के पेमेन्ट में ईरान को देते हैं। निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जिम्मेवारी हमारी है। ईरान द्वारा रुपये में पेमेन्ट लेने में हम इस जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं।

तेल के लिये मिले रुपयों से ईरान कपड़े, अनाज अथवा अन्य दूसरा माल भारत से खरीद सकता है। यह सौदा भारत के लिये लाभप्रद है।

पांचवां बिन्दु विश्व अर्थव्यवस्था का है। पश्चिमी विशेषकों का आकलन है कि ईरान से तेल की सप्लाई बाधित होने पर विश्व अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। तेल के वैश्विक दाम बढ़ेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था मंद पड़ेगी और हमारे निर्यातों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। तेल के मूल्य बढ़ने से विश्व अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जितना घाटा जर्मनी एवं फ्रांस जैसे आयात करने वाले देशों को होगा

उतना ही मुनाफा रूस, सऊदी अरब एवं नाइजीरिया जैसे निर्यातक देशों को होगा। विश्व अर्थव्यवस्था का ग्रोथ सेन्टर आयात करने वाले देशों से हटकर निर्यात करने वाले देशों की ओर बढ़ेगा।

सब्जी महंगी होने से किसान को लाभ और मध्य वर्ग को हानि होती है परन्तु अर्थव्यवस्था पर विशेष असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार तेल के दाम से देश विशेष को लाभ एवं हानि होगी परन्तु विश्व अर्थव्यवस्था पर न्यून प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो निर्यात जर्मनी और फ्रांस को जा रहे हैं उनकी दिशा ईरान, नाइजीरिया, रूस तथा वेनेजुएला की ओर मुड़ेगी। परन्तु हमें भी दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा जिससे हानि होगी।

छठा बिन्दु अमरीका की नाराजगी का है। ईरान से आयात जारी रखने पर अमरीका हमसे नाराज हो जायेगा

हमें अपनी उर्जा की खपत घटानी ही होगी। ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हो। अपनी भूमि पर उत्पन्न होने वाली उर्जा से अधिक खपत करने का कारण हम आयातों पर आश्रित हो जायेंगे और हमारी उर्जा सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी. . .

और उससे हमें मिलने वाली पूंजी तथा तकनीक बाधित होगी। मेरी दृष्टि से यह प्रभाव नगण्य होगा। भारत पूंजी का निर्यातक बन चुका है। हमारे उद्यमियों द्वारा विदेशों में निवेश अधिक किया जा रहा है। फिर भी जो पूंजी आ रही है उसमें कटौती होने की सम्भावना है।

वर्तमान में आधुनिक तकनीकों मे अमरीका अग्रणी है। अमरीका की यह अगुआई कुछ धीमी पड़ रही है परन्तु अभी अमरीका बहुत आगे है। ईरान से तेल का आयात जारी रखने से आधुनिक तकनीकों का मिलना कठिन हो जायेगा।

अन्ततः हमें अपनी उर्जा की खपत घटानी ही होगी। ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हो। अपनी भूमि पर उत्पन्न होने वाली उर्जा से अधिक खपत करने का कारण हम आयातों पर आश्रित हो जायेंगे और हमारी उर्जा सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी। अतः हमें उर्जा की सप्लाई को दो समानान्तर चैनलों में करना चाहिये जैसे एलपीजी के डोमेस्टिक और कामर्शियल सिलेंडर अलग–अलग होते हैं। मूलभूत जरूरतों जैसे रेलवे आदि के लिये उर्जा को पहले उपलब्ध कराना चाहिये। एयरकंडीशंड माल के स्थान पर अस्पताल आदि को प्राथमिकता देते हुये उर्जा की अनुत्पादक खपत को कम करना ही उर्जा संकट से उबरने का अंतिम उपाय है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022